

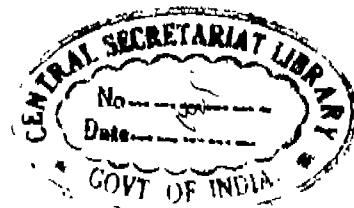


# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 211 ]  
No. 211 ]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 1996/अग्रहायण 20, 1918  
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 1996/AGRAHAYANA 20, 1918

उद्घोग मंत्रालय  
(सरकारी उद्घोग विभाग)  
संकल्प  
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1996

सं. 2( 15 )/95-मजूरी कक्ष :—भारत सरकार विगत कुछ समय से सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना में विछले कुछ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार करती रही है। 1-1-1992 से किए गए पिछले वेतन पुनरीक्षण के बाद से स्थितियां कई मामलों में बदल गई हैं। तदनुसार, वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

|            |  |
|------------|--|
| अध्यक्ष    | न्यायमूर्ति श्री एस. मोहन (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) |
| सदस्य      | श्री एस. बैंकिटारमणन, भूतपूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया        |
|            | डॉ. दीपक नायर, भूतपूर्व आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार                   |
|            | श्री दीपक पारीख, अध्यक्ष, आवास विकास एवं वित्त पोषण                  |
| सदस्य सचिव | श्री पी. जी. मांकड, सचिव, सरकारी उद्घोग विभाग                        |

समिति केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निम्नलिखित प्रेणी के कार्यपालकों को दिए जाने वाले सम्पूर्ण पैकेज, जिसमें गैर-मौद्रिक प्रकृति वाले भी शामिल होंगे, को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन, भर्ते, अनुलाभों तथा अन्य लाभों की संरचना पर विचार करेगी तथा उन परिवर्तनों के सम्बंध में सुझाव देगी, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हो :

- (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालक
- (ii) निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालक, तथा
- (iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ

अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समिति पांचवें बैतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

सरकार अपने विचारानुसार आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग तथा सभी जो आवश्यक सहयोग दे पाने की स्थिति में हों और वैसा कर सकने को स्वतंत्र हों, ऐसी संबद्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे जो समिति के लिए अपेक्षित हों।

समिति छः माह की अवधि के भीतर अपनी अनुशंसाएं कर देगी।

समिति की अनुशंसाओं के बारे में सरकार के निर्णय 1-1-1997 से लागू होंगे।

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

**MJNISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Public Enterprises)**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 10th December, 1996

**No. 2(15)/95-WC.**—The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the structure of emoluments of Public Sector executives over the years. Conditions have also changed in several respects since the last pay revision made with effect from 1-1-1992. Accordingly, it has been decided to appoint the Pay Revision Committee comprising the following :

|          |   |
|----------|---|
| Chairman | Shri Justice S. Mohan (Retd. Judge, Supreme Court)                      |
| Members  | Shri S. Venkitaraman, ex-Governor, RBI                                  |
|          | Dr. Deepak Nayyar, ex-Chief Economic Adviser, Government of India       |
|          | Shri Deepak Parekh, Chairman, Housing Development & Finance Corporation |

Member Secretary      Shri P. G. Mankad, Secretary, Department of Public Enterprises

The Committee will examine the present structure of pay, allowances, perquisites and benefits for the following categories of Central Government Public Sector executives, taking into account the total package of benefits available to them including non-monetary ones, and suggest changes therein which may be desirable and feasible :

- (i) Central Government PSUs Board level functionaries
- (ii) Below Board level executives
- (iii) Non-unionised supervisory staff

While finalising its report, the Committee will take into account the report of the Fifth Pay Commission.

The Committee will devise its own procedures as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India and State Governments will furnish such relevant information and documents as may be required by the Committee and which they are in a position and at liberty to give, and extend the necessary cooperation and assistance to it. The Committee will make its recommendations to the Government within a period of 6 months.

The decision of the Government on the recommendations of the Committee will take effect from 1-1-1997.

S. TALWAR, Jt. Secy.